भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2863

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल

2863. श्री के. सुधाकरनः

श्री हरीश चंद्र मीनाः

श्री मुरारी लाल मीनाः

डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर टोंक-सवाई माधोपुर जिलों सहित राजस्थान में भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन-कौन से क्षेत्रों में इसमें भारी ह्रास हुआ है;

(ख) भूजल ह्रास के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2024 के दौरान क्या विशिष्ट उपाय लागू किए गए/लागू किए जा रहे हैं, तथा जल शक्ति अभियान और 'कैच द रेन' अभियान जैसी पहलों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर राजस्थान सहित देश के गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों में, इन जल संरक्षण पहलों को लागू करने में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं;

(घ) इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और भूजल संरक्षण प्रयासों हेतु जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जल संरक्षण रणनितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों/अंतर्राष्ट्रीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राजस्थान सहित पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। देश में नवंबर 2023 के लिए मापे गए राज्यवार जल स्तर से यह ज्ञात होता है कि देश में लगभग 84.8% कूपों में भूजल स्तर से नीचे (एमबीजीएल) 0-10 मीटर की सीमा के पूरे जल स्तर के आंकड़े पाए गए हैं, जो भूजल की सुलभ उपलब्धता का संकेत हैं। नवंबर 2023 में पूरे देश के लिए जल स्तर की गहराई का राज्यवार वितरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राजस्थान राज्य में मॉनीटर किए गए 37% कुओं में 0-10 एमबीजीएल के मध्य जल स्तर दर्ज किया गया है और टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में क्रमश: 78.2% और 52.9% कुएं उक्त रेंज में जल स्तर की गहराई प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान राज्य के संबंध में नवंबर 2023 के लिए जल स्तर तक गहराई का जिलावार वितरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, वर्ष 2024 में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन 'नारी शक्ति से जल शक्ति' विषय के साथ किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। प्राप्त परिणामों में, वर्ष 2019 से जेएसए के तहत कुल लगभग 1.05 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया है और वर्ष 2024 में राजस्थान में 1.14 लाख संरचनाओं के साथ अब तक (मार्च 2024 से) लगभग 18.86 लाख संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र का मानचित्रण पूरा कर लिया है, जिसका उद्देश्य जलभृत की प्रकृति और विशिष्टीकरण का चित्रण करना है। जिला-वार प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा की गई हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्ष 2024 में नैक्यूम 2.0 अध्ययन का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों, भूजल संदूषण से प्रभावित क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, शहरी समूहों, स्प्रिंग शेड, औद्योगिक समूहों आदि जैसे चिह्नित प्राथमिकताबद्ध क्षेत्रों में बहुत अधिक बारीकी से विस्तृत मैपिंग की जा रही है।

iii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी अपनी प्रमुख योजनाओं के तहत विभिन्न जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण गतिविधियों को निरंतर निधि प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं के अभिसरण में, भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है।

(ग): जल संरक्षण संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन में सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय भूमि अधिकार और स्वामित्व संबंधी मुद्दे, क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त सूचना का अभाव, जमीनी स्तर पर कुशल कार्मिकों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता, विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के मध्य अपर्याप्त समन्वय; समुदाय के मध्य विश्वास और उनके समर्पित सहयोग, राज्य और स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त संस्थागत क्षमताएं; निर्माण कार्य के बाद प्रचालन एवं रख-रखाव संबंधी कार्यों पर ध्यान न देना शामिल है।

(घ): चूंकि सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए बिना लंबे समय तक जल संरक्षण गतिविधि जारी नहीं रखी जा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन को सही अर्थों में जन आंदोलन बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

i. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मूल विषय भूजल संसाधनों का समुदाय आधारित स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन है तथा सतत सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से इसका उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है।

ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर-II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिनमें स्थानीय लोगों को वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जागरूक बनाया जाता है।

iii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए जा रहे हैं जो जल संबंधी मुद्दों से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

iv. जल शक्ति अभियान की व्यापकता को सुदृढ़ करने और देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थायित्वता के लिए एक समुदाय-संचालित अभियान का शुभारंभ किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और दायित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

(ङ): जल संरक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कार्य करते हैं। मंत्रालय द्वारा रोटरी इंडिया वाटर कंजर्वेशन ट्रस्ट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आदि जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अटल भूजल योजना के तहत, कई गैर सरकारी संगठनों को जिला कार्यान्वयन भागीदारों (डीआईपी) के रूप में शामिल किया गया है जो इस योजना के कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों और समुदाय के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय संघ, फिजिकलिश - टेकनिशे बुंडेसनस्टाल्ट (पीटीबी), ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड), ऑर्गेनाजेशन फॉर इंडसट्रीयल, सपीरिचुअल एंड कल्चरल एडवांसमेंट (ओआईएससीए) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न रूपों में मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

मानसून पश्चात 2023 के प्रेक्षण कूपों के प्रतिशत का राज्यवार जल स्तर की गहराई का वितरण (असंबंधित जलभृत)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) प्रदर्शित करने वाले कूपों की संख्या / प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	809	109	13.5	382	47.2	241	29.8	54	6.7	16	2.0	7	0.9
2	अरुणाचल प्रदेश	28	12	42.9	8	28.6	7	25.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
3	असम	318	125	39.3	156	49.1	30	9.4	6	1.9	1	0.3	0	0.0
4	बिहार	784	116	14.8	525	67.0	139	17.7	4	0.5	0	0.0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	1046	172	16.4	628	60.0	228	21.8	16	1.5	2	0.2	0	0.0
6	गोवा	82	17	20.7	38	46.3	21	25.6	6	7.3	0	0.0	0	0.0
7	गुजरात	753	105	13.9	305	40.5	215	28.6	96	12.7	26	3.5	6	0.8
8	हरियाणा	985	71	7.2	160	16.2	154	15.6	198	20.1	253	25.7	149	15.1
9	हिमाचल प्रदेश प्रदेश	171	30	17.5	69	40.4	30	17.5	26	15.2	12	7.0	4	2.3
10	झारखंड	396	51	12.9	216	54.5	114	28.8	8	2.0	7	1.8	0	0.0
11	कर्नाटक	1264	228	18.0	504	39.9	454	35.9	75	5.9	3	0.2	0	0.0
12	केरल	1377	323	23.5	477	34.6	485	35.2	85	6.2	5	0.4	2	0.1
13	मध्य प्रदेश	1470	151	10.3	654	44.5	501	34.1	147	10.0	12	0.8	5	0.3
14	महाराष्ट्र	1658	248	15.0	706	42.6	526	31.7	141	8.5	32	1.9	5	0.3
15	मेघालय	51	23	45.1	27	52.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	मिजोरम	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	नागालैंड	10	0	0.0	6	60.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
18	ओडिशा	1370	528	38.5	694	50.7	142	10.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0
19	पंजाब	283	29	10.2	55	19.4	34	12.0	65	23.0	81	28.6	19	6.7
20	**राजस्थान**	**1061**	**27**	**2.5**	**171**	**16.1**	**195**	**18.4**	**234**	**22.1**	**194**	**18.3**	**240**	**22.6**
21	तमिलनाडु	857	186	21.7	359	41.9	239	27.9	60	7.0	11	1.3	2	0.2
22	तेलंगाना	623	58	9.3	278	44.6	204	32.7	72	11.6	9	1.4	2	0.3
23	त्रिपुरा	96	26	27.1	57	59.4	13	13.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24	उत्तर प्रदेश	1092	179	16.4	481	44.0	265	24.3	133	12.2	30	2.7	4	0.4
25	उत्तराखंड	171	17	9.9	48	28.1	35	20.5	31	18.1	25	14.6	15	8.8
26	पश्चिम बंगाल	736	224	30.4	413	56.1	85	11.5	14	1.9	0	0.0	0	0.0
27	अंडमान और निकोबार	111	103	92.8	8	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28	चंडीगढ़	14	0	0.0	5	35.7	2	14.3	2	14.3	4	28.6	1	7.1
29	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	30	7	23.3	17	56.7	6	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	दिल्ली	119	9	7.6	30	25.2	39	32.8	26	21.8	11	9.2	4	3.4
31	जम्मू और कश्मीर	385	96	24.9	173	44.9	59	15.3	27	7.0	21	5.5	9	2.3
32	पुडुचेरी	9	2	22.2	5	55.6	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	**18161**	**3274**	**18.0**	**7655**	**42.2**	**4469**	**24.6**	**1534**	**8.4**	**755**	**4.2**	**474**	**2.6**

*****

अनुलग्नक-II

"भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

मानसून पश्चात 2023 के प्रेक्षण कूपों के प्रतिशत के जल स्तर की गहराई का जिलावार वितरण (अपरिरुद्ध जलभृत)

क्र सं	जिले का नाम	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) प्रदर्शित करने वाले कूपों की संख्या / प्रतिशत											
			0 to 2		2 to 5		5 to 10		10 to 20		20 to 40		> 40	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अजमेर	17	0	0.0	8	47.1	3	17.6	1	5.9	5	29.4	0	0.0
2	अलवर	19	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	26.3	7	36.8	6	31.6
3	अनूपगढ़	5	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
4	बालोतरा	9	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	22.2	5	55.6	0	0.0
5	बांसवाड़ा	33	1	3.0	14	42.4	13	39.4	5	15.2	0	0.0	0	0.0
6	बारां	14	1	7.1	6	42.9	6	42.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0
7	बाड़मेर	34	0	0.0	1	2.9	4	11.8	6	17.6	12	35.3	11	32.4
8	ब्यावर	11	0	0.0	2	18.2	4	36.4	4	36.4	1	9.1	0	0.0
9	भरतपुर	19	1	5.3	2	10.5	4	21.1	4	21.1	4	21.1	4	21.1
10	भीलवाड़ा	50	0	0.0	15	30.0	10	20.0	19	38.0	5	10.0	1	2.0
11	बीकानेर	40	0	0.0	0	0.0	4	10.0	13	32.5	12	30.0	11	27.5
12	बूंदी	10	1	10.0	4	40.0	4	40.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
13	चित्तौड़गढ़	14	3	21.4	0	0.0	4	28.6	5	35.7	2	14.3	0	0.0
14	चुरू	27	0	0.0	0	0.0	1	3.7	5	18.5	13	48.1	8	29.6
15	दौसा	30	0	0.0	0	0.0	1	3.3	14	46.7	5	16.7	10	33.3
16	डीग	9	0	0.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0.0
17	धौलपुर	19	0	0.0	7	36.8	3	15.8	3	15.8	5	26.3	1	5.3
18	डीडवाना कुचामन	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	31.6	8	42.1	5	26.3
19	दूदू	24	1	4.2	8	33.3	10	41.7	4	16.7	1	4.2	0	0.0
20	डूंगरपुर	17	1	5.9	7	41.2	8	47.1	1	5.9	0	0.0	0	0.0
21	गंगानगर	31	0	0.0	2	6.5	8	25.8	13	41.9	6	19.4	2	6.5
22	गंगापुर शहर	12	0	0.0	4	33.3	2	16.7	5	41.7	0	0.0	1	8.3
23	हनुमानगढ़	31	2	6.5	0	0.0	1	3.2	11	35.5	14	45.2	3	9.7
24	जयपुर	13	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	2	15.4	8	61.5
25	जयपुर (ग्रामीण)	73	0	0.0	2	2.7	8	11.0	11	15.1	12	16.4	40	54.8
26	जैसलमेर	55	0	0.0	1	1.8	6	10.9	11	20.0	22	40.0	15	27.3
27	जालोर	6	0	0.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3
28	झालावाड़	24	0	0.0	6	25.0	13	54.2	5	20.8	0	0.0	0	0.0
29	झुंझुनू	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7	21	91.3

30	जोधपुर	7	0	0.0	2	28.6	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3
31	जोधपुर (ग्रामीण)	48	0	0.0	8	16.7	5	10.4	12	25.0	8	16.7	15	31.3
32	करौली	27	1	3.7	2	7.4	4	14.8	7	25.9	11	40.7	2	7.4
33	केकरी	7	0	0.0	2	28.6	3	42.9	2	28.6	0	0.0	0	0.0
34	खैरथल -तिजारा	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	62.5	3	37.5
35	कोटा	16	3	18.8	4	25.0	4	25.0	3	18.8	2	12.5	0	0.0
36	कोटपुतली -बहरोड़	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	10	71.4
37	नागौर	20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	20.0	2	10.0	14	70.0
38	नीम का थाना	3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
39	पालि	18	2	11.1	7	38.9	6	33.3	3	16.7	0	0.0	0	0.0
40	फलोदी	13	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0.0	10	76.9
41	प्रतापगढ़	15	3	20.0	4	26.7	5	33.3	3	20.0	0	0.0	0	0.0
42	राजसमंद	27	1	3.7	14	51.9	6	22.2	6	22.2	0	0.0	0	0.0
43	सलूंबर	10	2	20.0	3	30.0	2	20.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0
44	सांचौर	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	33.3	4	44.4
45	**सवाई माधोपुर**	**17**	**0**	**0.0**	**3**	**17.6**	**6**	**35.3**	**6**	**35.3**	**1**	**5.9**	**1**	**5.9**
46	शाहपुरा	12	1	8.3	4	33.3	4	33.3	3	25.0	0	0.0	0	0.0
47	सीकर	41	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	9	22.0	30	73.2
48	सिरोही	13	0	0.0	4	30.8	5	38.5	4	30.8	0	0.0	0	0.0
49	**टोंक**	**23**	**0**	**0.0**	**9**	**39.1**	**9**	**39.1**	**3**	**13.0**	**2**	**8.7**	**0**	**0.0**
50	उदयपुर	25	3	12.0	10	40.0	6	24.0	6	24.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	**1061**	**27**	**2.5**	**171**	**16.1**	**195**	**18.4**	**234**	**22.1**	**194**	**18.3**	**240**	**22.6**

*****